ग्लोबल इंडिया

'मांस खाते भगवान गणेश' के विज्ञापन पर विवाद, भारत ने जताया विरोध

कैनबरा। मेमने का मांस खाते भगवान गणेश वाले विज्ञापन पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने

कूटनीतिक विरोध दर्ज करवाया है। ऑस्ट्रेलिया के 3 सरकारी विभागों, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशंस और ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कैनबरा स्थित भारतीय उच्चायोग ने मीट एंड लाइवस्टॉक ऑस्ट्रेलिया के विवादित ऐड को लेकर विरोधपत्र भेजते हुए इस मामले में एक्शन लेने को कहा है। इसमें कहा गया है कि इस विज्ञापन से भारतीय समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के विरोध का संज्ञान लेते हुए भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि मांस उत्पादक समूह मीट एंड लाइवस्टॉक ऑस्ट्रेलिया का यह विज्ञापन अपमानजनक है जिसने भारतीय समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत की हैं। हाल ही में रिलीज किए गए इस वीडियो में भगवान गणेश दूसरे धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ मेमने का मीट खाते हुए दिखाई देते हैं। उच्चायोग ने बताया कि भारतीय समुदाय इस बात को लेकर नाराज है कि भगवान गणेश कभी मांसाहार नहीं करते हैं और न ही उन्हें कभी मांस चढ़ाया जाता है। भारतीय उच्चायोग ने बताया कि सिडनी में भारत के महावाणिज्य दूत ने इस मामले को सीधे मीट एंड लाइवस्टॉक ऑस्ट्रेलिया के समक्ष उठाते हुए उनसे इस ऐड को हटाने की मांग की है। कई सामुदायिक संगठनों ने भी ऑस्ट्रेलिया की सरकार और मीट एंड लाइवस्टॉक ऑस्ट्रेलिया के सामने विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलिया की हिंदू परिषद ने मेमने के मांस की खपत को बढ़ाने के लिए भगवान गणेश की तस्वीर के इस्तेमाल को भौंडा और घिनौना प्रयास बताया है।

संयुक्त राष्ट्र ने उ. कोरिया पर लगाए सबसे कड़े प्रतिबंध

15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से दी मंजूरी

न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने पर सबकी सहमति से मंजूरी दे दी है। ये प्रतिबंध 3 सितम्बर को किए गए छठे और सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन टेस्ट के बाद लगाए गए हैं। इसके तहत नॉर्थ कोरिया पर कच्चे तेल के इम्पोर्ट और कपड़ों के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लग गया है।

नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर उसके खिलाफ 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का यह नौंवा प्रतिबंध है। यूएन में अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने कहा, अगर नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगाता है तो भविष्य में प्रतिबंधों को वापस लिया जा सकता है।

हेली ने कहा कि अगर वह खतरनाक रास्ते पर लगातार चलते रहेगा, तो हम उस पर निरंतर और भी दबाव बनाते रहेंगे। उन्होंने उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रतिबंध प्रस्ताव के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच मजबूत संबंधों को श्रेय दिया। दूसरी तरफ रूस ने मौजूदा संकट के समाधान के लिए बिना किसी राजनीतिक पहल के नॉर्थ कोरिया के खिलाफ प्रतिबंधों को और कड़ा किए जाने की निंदा की है।

फिलहाल युद्ध की जरूरत नहीं

हेली ने कहा है कि उनका देश उत्तर कोरिया के खिलाफ युद्ध छेड़ने की योजना नहीं बना रहा है क्योंकि उत्तर कोरिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अब तक ऐसे मोड़ पर नहीं पहुंचा है जहां से वापसी संभव नहीं हो।

शांति बनाए रखने की गुजारिश

संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत लियू जिएई ने उत्तर कोरिया से न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट रोकने को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की उम्मीदों और इच्छाओं को गंभीरता से लेने की अपील की है और सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की गुजारिश की है। लियू ने कहा कि संबंधित पक्षों को जितना जल्दी हो सके फिर से बातचीत शुरू करनी चाहिए।

पाक ने खेला चीन कार्ड, यूएस को प्रतिबंधों के खिलाफ दी धमकी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान पर आंतकवाद के सुरक्षित पनाहगाह होने के आरोपों के बाद यूएस की तरफ से आर्थिक मदद में शर्तें लागू होने पर अब इस्लामाबाद ने चीन कार्ड खेला है। प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा है कि पाकिस्तानी अधिकारियों को प्रतिबंधित करना या सैन्य सहायता में कटौती करना अमेरिका के लिए प्रतिकूल हो सकता है। अब्बासी ने चेतावनी दी कि इससे दोनों देशों की आतंकवाद के खिलाफ जारी लड़ाई पर भी असर पड़ेगा। बीते महीने अफगानिस्तान पर यूएस की नई रणनीति की घोषणा के समय राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर लताड़ा था, जिसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव है। अब्बासी ने कहा, 'हम आतंकवाद के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, हमारी कोशिशों को कुछ भी नुकसान पहुंचा तो इससे अमेरिका की कोशिशों को ही नुकसान होगा।' अमेरिका ने बीते साल पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर से भी कम सैन्य सहायता दी है जबकि 2011 में यह राशि 3.5 अरब डॉलर थी। अब्बासी ने वॉशिंगटन को इस पर चेताया कि पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद में कटौती कर के अमेरिका कभी भी अपने आतंकविरोधी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकेगा।

मिस्र के सिनाई में हमला, 18 पुलिसकर्मी मरे

काहिरा। मिस्र के उत्तर सिनाई के अशांत अल आरिश शहर में कथित इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने हमला कर 18 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। आईएस लड़ाकों ने पुलिस के काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 18 पुलिसकर्मी मारे गए और आठ अन्य घायल हुए। सड़क किनारे लगाए गए बम से बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया गया और उनमें से तीन को आग लगा दी। हथियारबंद चरमपंथियों ने पुलिसकर्मियों को घेरकर उनपर अंधाधुंध गोलीबारी की। आंतरिक मंत्रालय ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि इसमें कई पुलिसकर्मियों की मौत हुई है।

रोहिंग्या मुसलमानों को सुदूर बंजर द्वीप पर बसाएगा ढाका

ढाका। म्यांमार में हिंसा के बाद वहां से भागे हजारों रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों को बांग्लादेश के एक बंजर द्वीप पर अपना नया आशियाना बसाने पर मजबूर होना पड़ सकता है। उस द्वीप पर हर साल बाढ़ आती है। बांग्लादेश सरकार ने रोहिंग्या मुस्लिमों को उस द्वीप पर पहुंचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मदद की अपील की है, क्योंकि म्यांमार के रखाइन प्रांत में सैन्य कार्रवाई के बाद से गरीबी से जूझ रहे बांग्लादेश में बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम शरण की आस में पहुंच रहे हैं और उन्हें बसाने को लेकर

अधिकारियों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। रखाइन प्रांत में गत 25 अगस्त से शुरू हुए हिंसा के नए दौर के बाद से बांग्लादेश में तीन लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमान आ गए हैं। लगभग तीन लाख शरणार्थी पहले से ही म्यांमार सीमा के निकट कॉक्स बाजार जिले में संयुक्त राष्ट्र के शिविरों में रह रहे हैं। म्यांमार से बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने पर बांग्लादेश के अधिकारियों को और शिविर बनाने के लिए स्थान खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। रोहिंग्या नेताओं और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के अनिच्छुक होने के बावजूद बांग्लादेश के अधिकारी गैर आबादी वाले थेनगार छार द्वीप पर भी शिविर बनाने पर विचार कर रहे हैं। इस द्वीप का हाल में नाम बदलकर भासान छार किया गया था।

अमेरिकी कोर्ट का फैसला

बंदर की सेल्फी से होने वाली कमाई का एक हिस्सा बंदरों के कल्याण पर होगा खर्च

सेन फ्रांसिस्को। सेल्फी बंदर ने ली, अब उस पर अधिकार किसका?

इस अनोखे सवाल का जवाब संघीय अपीली अदालत देती उससे पहले ही अटॉर्नी ने घोषणा कर दी कि सेल्फी तस्वीर के कॉपीराइट मामले का निबटारा हो गया है। समझौते के तहत, जिस फोटोग्राफर के कैमरे का इस्तेमाल तस्वीर लेने के लिए हुआ था उसने भविष्य में तस्वीरों से मिलने वाले राजस्व का 25 फीसदी अंश इंडोनेशिया में बंदरों की विशेष प्रजाति के संरक्षण का काम करने वाली धर्मार्थ संस्थाओं को देने पर सहमति जताई है। प्राणी-अधिकार समूह के वकीलों ने यह जानकारी दी। अटॉर्नी और फोटोग्राफर डेविड स्लाटर ने सान फ्रांसिस्को स्थित नाइंथ यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स से मामले को निरस्त करने और निचली अदालत के उस फैसले को रद्द करने को कहा जिसमें कहा गया था कि कॉपीराइट का अधिकार प्राणियों को नहीं मिल सकता है। स्लाटर के अटॉर्नी एंड्रयू जे धुये ने यह बताने से इनकार कर दिया कि तस्वीरों से कितनी कमाई हुई और क्या उनके मुवक्किल भविष्य की कमाई का पूरा 75 फीसदी अंश अपने पास रखेंगे। अदालत ने तत्काल कोई फैसला नहीं दिया है।

सांप से भी ज्यादा जहरीला पौधा

लंदन। ब्रिटेन के लंकाशायर में नदी किनारे एक ऐसा पौधा मिला है, जिसे छूते ही हाथों में फफोले पड़ जाते हैं। दरअसल, जाइंट होगवीड नामक यह पौधा काफी

विषैला माना गया है। ब्रिटेन में पहली बार यह पौधा 19वीं शताब्दी में मिला था। इसके बाद वह अब कुछ दिनों पहले नदी के किनारे मिला। शहर में रहने वाले एक 11 वर्षीय बच्चे ने इस पौधे को छू लिया, जिसके बाद उसके हाथों में फफोले पड़ गए। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया।

इस जहरीले पौधे का रंग सफेद और हरा है। वहीं, शहर में रहने वाले कुछ लोगों का कहना है कि यह पौधा उनके घर के आसपास भी देखा गया है। उन्होंने पड़ोसियों और बच्चों से इस पौधे से दूर रहने के लिए कहा है।

स्थानीय निवासी पीटर नील्सन ने कहा, लोगों को इस पौधे के बारे में सतर्क रहने की जरूरत है। यह बहुत खतरनाक है। इसे रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। पिछले साल दो स्कूली छात्रों को भी अस्पताल भेजा गया था, जब उनकी स्किन इस पौधे की संपर्क में आ गई थी। गौरतलब है कि यह पौधा रोशनी में किसी स्किन के संपर्क में आने के बाद जहरीला रसायन छोड़ता है। यदि गलती से भी इस पौधे के संपर्क में आ गए हैं, तो फौरन उसे साबुन और पानी से धो लें। इसके बाद पास के डॉक्टर को दिखाएं।

पाक की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर अमेरिका को टेंशन

वॉशिंगटन। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान अब अमेरिका के निशाने पर है। कांग्रेस की एक समिति ने अफगानिस्तान में अमेरिकी लक्ष्यों के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को लेकर चिंता जताते हुए उसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मानदंडों पर खरा उतरने को कहा है। अप्रोपिएशन्स कमेटी ने सेनेट और सदन में प्रस्ताव रखा है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य और आर्थिक दोनों प्रकार की सहायता के लिए कड़ी शर्तें तय की जानी चाहिए।

2018 के लिए विदेश मंत्रालय का वार्षिक विनियोग विधेयक पारित करते हुए कमेटी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सहित, क्षेत्र में अमेरिकी लक्ष्यों के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता चिंता का विषय है।